



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, संगलवार, ९ फरवरी, १९९३/२० माघ, १९१४

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुदेशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, ३ फरवरी, १९९३

संख्या विद्युत-४(५) ४/९२.—यतः भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ (१८९४ का पहला अधिनियम) की धारा-३ के खण्ड (सी०सी०) के अर्थात् गंत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एह नियम है के द्वारा अपने व्यव पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पारली कररी, उप-तहसील वाली चौकी, जिला मण्डी में १३२ के० वी० डब्बल सर्कट संचार लाईन लाइजी-गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ६ के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा ७ के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश देने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, भू-अर्जुन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विजली बोर्ड, मण्डी, ज़िला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

ज़िला : मण्डी

उप-तहसील : बाली चौकी

ग्राम	खसरा नं०	क्षत्रफल बीघों में
पारली करेरी	716/26/1	0-8-9

आदेशानुसार,
वित्तायुक्त एवं सचिव।